

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 380]	दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 24, 2017/कार्तिक 2, 1939	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 293
No. 380]	DELHI, TUESDAY, OCTOBER 24, 2017/KARTIKA 2, 1939	[N.C.T.D. No. 293

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

आदेश

दिल्ली, 24 अक्टूबर, 2017

सं. फा. 7/78/एडीएलबी/श.वि./2016/7242-63.—दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (यथासंशोधित) की धारा 116 की उपधारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 1 फरवरी, 2017 की अधिसूचना सं. 7/78/एडीएलबी/श.वि./2016/627-29 तथा दिनांक 3 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना सं. 7/78/एडीएलबी/श.वि./2016/पार्ट फाइल-1/2034-55 के अनुक्रम में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल चतुर्थ नगर मूल्यांकन समिति (यहां बाद में "समिति" के रूप में उल्लिखित) का पुनर्गठन करते हैं तथा उसकी अवधि बढ़ाते हैं, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:—

- | | |
|--|---------|
| 1. श्री जी. एस. पटनायक, आईएएस, एजीएमयूटी-1980 (सेवानिवृत्त) | अध्यक्ष |
| 2. सुश्री शिप्रा मैत्रा | सदस्य |
| 3. प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार | सदस्य |
| 4. अतिरिक्त आयुक्त, दक्षिण दिल्ली नगर निगम में संपत्ति कर विभाग के प्रभारी | सदस्य |
| 5. अतिरिक्त आयुक्त, उत्तर दिल्ली नगर निगम में संपत्ति कर विभाग के प्रभारी | सदस्य |
| 6. अतिरिक्त आयुक्त, पूर्व दिल्ली नगर निगम में संपत्ति कर विभाग के प्रभारी | सदस्य |

1. अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य पूर्णकालिक सेवा प्रदान करेंगे और वे उस तारीख से जब से वे कार्यभार संभालते हैं, समिति का कार्यकाल समाप्त होने तक अपने पद पर बने रहेंगे।

2. समिति के कार्य निम्नलिखित होंगे:—

(क) दिल्ली नगर निगम को दिल्ली के किसी भी वार्ड में खाली भूमि और भवनों को कॉलोनियों और भू-समूहों और भवनों में वर्गीकरण से संबंधित मामलों पर निगम को सिफारिश करना तथा खाली भूमि के प्रति ईकाई क्षेत्रफल मूल्य या भवनों के आच्छादित स्थान का प्रति ईकाई

क्षेत्रफल के आधार मूल्य का निर्धारण तथा इसमें वृद्धि करने या कमी करने या वृद्धि न करने या कमी न करने के कारक ;

(ख) दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (यथासंशोधित) की धारा 116ग के अधीन आपत्तियों पर विचार करना तथा उनकी सिफारिश करना, तथा

(ग) ऐसे सभी कार्यों का निष्पादन जो सरकार द्वारा अपेक्षित हो।

3. समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते इत्यादि दिल्ली नगर निगम (नगर मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा शर्तें) नियमावली, 2003 के अनुसार निर्धारित किये जायेंगे।
4. समिति कार्यकाल 18 फरवरी, 2018 तक होगा, जिसमें वह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
5. दक्षिण दिल्ली नगर निगम आवश्यक आधारभूत संरचना तथा सचिवालय सहायता उपलब्ध करायेगी तथा समिति के कार्यों के लिये अपेक्षित व्यय को पूरा करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

पवन चौपड़ा, उप-निदेशक (स्थानीय निकाय)

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

ORDER

Delhi, the 24th October, 2017

No. F. 7/78/ADLB/UD/2016/7242-63.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (3) of section 116 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (as amended), and in continuation of Notification No.F.7/78/ADLB/UD/2016/627-29 dated 1st February, 2017 and Notification No. F. 7/78/ADLB/UD/2016/PF-1/2034-55 dated 3rd April 2017, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to reconstitute and extend the term of Fourth Municipal Valuation Committee (hereinafter referred to as “Committee”), consisting of the following:—

- | | |
|--|---------------|
| 1. Shri G.S. Patnaik, IAS, AGMUT-1980 (Retd) | - Chairperson |
| 2. Ms. Shipra Maitra | - Member |
| 3. Principal Secretary (Finance),
Government of the National Capital Territory of Delhi | - Member |
| 4. Additional Commissioner,
In-charge of the Property Tax Deptt. in South DMC | - Member |
| 5. Additional Commissioner,
In-charge of the Property Tax Deptt. in North DMC | - Member |
| 6. Additional Commissioner,
In-charge of the Property Tax Deptt. in East DMC | - Member |

2. The Chairperson and other members shall render full-time service to the Committee and shall hold office from the date on which they respectively assume their office up to the closure of the term of the Committee.

3. The functions of the Committee shall be –

- a) to make recommendations to the Municipal Corporation of Delhi on matters relating to classification of vacant lands and buildings in any ward of Delhi into colonies and groups of

- lands and buildings and fixation of base value per unit area of vacant land or per unit area of covered space of building and factors for increase or decrease, or for no increase or decrease, thereof;
- b) to consider objections under section 116 C of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (as amended) and to make recommendations thereon, and
 - c) to perform such other function as the Government may require.
4. The salaries, allowances etc. of the Chairperson and Members of the Committee shall be determined as per Delhi Municipal Corporation (Conditions of Service of the Chairperson and Members of the Municipal Valuation Committee) Rules, 2003.
5. The tenure of the Committee shall be till 28th February 2018, within which it shall submit the report.
6. The South Delhi Municipal Corporation of Delhi shall provide necessary infra-structure and Secretariat support and meet the required expenditure for the functioning of the Committee.

By Order and in the Name of Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

PAWAN CHOPRA, Dy. Director (Local Bodies)